

सत्ता की स्तुति नहीं, सत्ता से सवाल चाहिए



अच्छा पत्रकार वह नहीं जो बड़े नेताओं के साथ स्तुति लिख कर फेंकसुकर पर पोस्ट करे, बल्कि वह है जो बड़े नेताओं की अच्छी से खिंचाई करती हुई रिपोर्ट को पोस्ट करे - यह एक वाक्य आज की पत्रकारिता की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी सच्चाई बन गया है। फेंकसुकर खोलिए तो पत्रकार कम और दलबारी ज्यादा दिखते हैं। हर प्रोफाइल पर एक ही दृश्य, किसी नवीं के साथ मुकुटपुरी हुई सेल्फी, किसी विषयक के कथे पर बह, किसी बड़े नेता से सम्मान लेते हुए फोटो और नीचे लिखा होता है आलमिय भेंट, मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, धन्य हो गया। लहक और वाह-वाह की बौछार में यह सवाल कहीं दब जाता है कि अधिकार पत्रकार का काम क्या है, नेता के मन में खड़े होकर अपनी पहुँच दिखाना या नेता के सामने खड़े होकर जनता के सवाल पूछना। यह फोटो अब वह नहीं रही, यह एक सर्टिफिकेट बन गई है, एक धीस बन गई है जो धनेश्वर को, लेखपाल को, ठेकेदार को दिखाने के काम आती है कि देखो मेरी पहुँच कितनी ऊपर तक है और जिस दिन पत्रकार खबर की साख को जगह संपर्क की धाक से काम चलाते लगे, उसी दिन वह पत्रकार नहीं रह जाता, वह जनसर्जन अधिकारी बन जाता है। उसकी कलम में स्याही नहीं होती, सत्ता का डर रहता है और वह सवाल मुक़्त भूल जाता है।

पत्रकारिता का जन्म ही सत्ता की आरती उतारने के लिए नहीं था, सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल पूछने के लिए हुआ था। पंडित नेहरू ने कहा था मैं चाहता हूँ प्रेस भी आलोचना करे, यह उदरता नहीं थी, यह लोकतंत्र की समझ थी। अगर प्रेस सत्ता का भजन गाएगा तो सत्ता बड़ी और अंधी हो जाएगी। अमेरिका का वाटरगेट कोई बाद कीजिए, दो पत्रकारों ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों को कुर्सी छोड़ने

पर मजबूर कर दिया था, वह नेता के साथ फोटो खिंचवाकर नहीं हुआ था, बल्कि नेता की फाइलों की फोटो खिंचकर हुआ था। भारत में भी बोफोर्स से लेकर कॉमनवेल्थ तक, चारा घोटाला से लेकर व्यापम तक हर बड़ी खबर एक अरुण करने वाली रिपोर्ट थी, एक असुविधाजनक सवाल था। किसी ने घोटालेबाज के साथ सेल्फी डालकर इतिहास नहीं बनाया। अच्छा पत्रकार वह है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हथ हिलाने के लिए नहीं, हथ उठकर कहने के लिए जाता है कि सर, आपके आंकड़े और जमीन की हकीकत में अंतर है।

खिंचाई का मतलब गाली या ट्रेलिंग नहीं है, खिंचाई का मतलब है तथ्य, तर्क और समुचित साधन जवाबदेही तक करना। अगर सरकार कहती है हमने तो स्कूल बनाए, तो पत्रकार का काम पोस्टर छापना नहीं, जाकर गिनना है कि कितने बने, कितनों में शिक्षक हैं, कितनों की छत टपकती है। अगर कहा जाता है अश्या खस हो गया, तो धाने के रजिस्टर, पीछि के आंसू और एससीआरबी के आंकड़े सामने रखना ही पत्रकारिता है। यह खिंचाई नकरत से नहीं, जिम्मेदारी से पैदा होती है क्योंकि पत्रकार का बाँस नेता नहीं, जनता है। सोशल मीडिया ने एक नया धम और नया तालचक पैदा कर दिया है। अब हर पत्रकार खर एक छोटा नेता बनना चाहता है, उसे भी फ्लोअर चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए और सबसे असरान हैंडक्रेट है बड़े नेता के साथ फोटो। एलोगीरिड भी खुश, अहंकार भी खुश। लेकिन इस सरीरे में पत्रकार अपना सबसे बड़ा हथियार गंवा देता है, वह है विश्वसनीयता। पाठक अब बेवकूफ नहीं वह, वह सब देखता और समझता है। वह जानता है कि जो पत्रकार हर दिन किसी न किसी नेता की गोद में बैठा दिख रहा है, वह उसी नेता के खिलाफ खबर कैसे लिखेगा। वह आसानी फोटो पर बह करेगा, लेकिन आसानी खबर पर भरोसा नहीं करेगा। नेता भी वह खेत खूब समझता है, वह जानता है कि पत्रकार को फोटो का टुकड़ा फेंके, वह सवाल भूल जाएगा। इसलिए वह फोटो देता है और खबर ले लेता है। यह पत्रकारिता नहीं, एक सौदा है। और इस सरीरे में अंत में लोकतंत्र हलता है। आज की गरीब में सत्ता के पास अपना आईटी सेल है, अपनी प्रचार मशीनी

है, उसे आपके प्रचार की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत है आपके सवाल की, ताकि वह सुपर संकेतो अच्छा पत्रकार कैसे दिखता है? वह फेंकसुकर पर कम चमकता है, फोल्ड में जगह खटता है। उसकी चाल पर नेता के साथ दस फोटो नहीं बल्कि दस ऐसे रिपोर्ट होती हैं जिनमें किसी मजबूर का रसना काँड़ अस्ताल में डंडकर की नुस्खी कवाई। वह सम्मान सम्मान में मंच पर बैठने के लिए नहीं दौड़ता, वह उस सम्मान के खर्च का आर्टीआई लगाता है। वह इस विचार को जस का तस कॉपी-पेस्ट नहीं करता, वह उसे तीन पत्र करके क्रॉस-चेक करता है। वह डरता है, क्योंकि सत्ता से टकराना आसान नहीं है, उसे धमकी भी मिलती है, ब्रिडायन भी रकता है, सोशल मीडिया पर ट्रेल आभी भी पीछे चढ़ती है, लेकिन फिर भी वह लिखता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वह नहीं लिखेगा तो कोई नहीं लिखेगा। नेता आते-जाते रहेंगे, सरकारें बदलती रहेंगी, फेंकसुकर की टाइमलइन हर दो घंटे में बतल जाती है, आज जिसके साथ आपने गवं से फोटो खिंचवाई है कल वह बिपक्ष में होगा, तब क्या आप वह फोटो डिलीट कर दी लेकिन एक ईमानदार रिपोर्ट, एक सार्वभौमिक सवाल, एक गरीब के हक में लिखी गई खबर वह इतिहास में रहती है, लोग उसे सालों तक याद रखेंगे। इसलिए युवा पत्रकारों से, स्वच्छर उन साथियों से जो अभी इस पेरे में आए हैं, एक ही निवेदन है, कैसा नेता की ओर नहीं, जनता की ओर घुमाओ। फोटो नेता के साथ नहीं, उस टाइटल स्ट्रक, उस सुखे लाल, उस खाली बलासूम के साथ खिंचवाओ जिसके लिए तुमने लिखा है। फेंकसुकर पर लाइक फोटो को फोटो से मिसेगे, लेकिन इज्जत नेता को खिंचाई करने वाली रिपोर्ट से मिलेगी और इस पेरे में अंत में इज्जत ही बचती है, लाइक नहीं। लोकतंत्र में पत्रकार का काम सत्ता की बगल में नाचना नहीं है, बगल में हो रहे बिजली चोरी फड़कना है।

डॉ. शैलेश शुक्ला

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा १४ राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित

साधनावादी सूत्रधार न्यास के

तत्वावधान में साधना वाणी पत्रिका का मूल्य विमोचन

साधनावादी साहित्य की वैचारिक यात्रा को एक नई दिशा प्रदान करने वाली 'साधना वाणी' ई-पत्रिका के तृतीय अंक माह अक्टूबर 2026 का आभासी विमोचन नवरात्रि के प्रथम दिन दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को रात्रि 9-00 बजे आभासी माध्यम से अत्यंत गरिमामय एवं साहित्यिक वातावरण में सम्पन्न हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अनेकानेक साहित्यकारों की विद्वानों एवं साहित्य प्रेमियों ने उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक अवसर को साक्षी भाव से गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ। इसके पश्चात् डॉ. कृष्ण कांत मिश्र ने सभी अग्रागत अतिथियों, साहित्यकारों एवं साहित्यप्रेमियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। तत्पश्चात् डॉ. लक्कड़ तिवारी माधवपुरी ने अपनी मोहक, शानदार एवं प्रभावशाली शैली में 'साधना वाणी' ई-पत्रिका के अंक 3 माह अक्टूबर 2026 का मूल्य विमोचन किया। इस अवसर पर देव अतिथि के रूप में पधारे डॉ. जय प्रकाश तिवारी, बलिया (उत्तर प्रदेश) के साधनावादी साहित्य के स्वरूप, उसकी अवधारणा एवं वर्तमान संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता को विस्तार से रेखांकित किया। उन्होंने साधनावादी साहित्यिक सूत्रधार न्यास के संस्थापक आचार्य डॉ. ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत के उल्लेखनीय योगदान एवं नवोदय परिवार के इस अभिनव साहित्यिक पहल एवं उसकी निरंतरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

आ. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय 'गडबड़ प्राणवाही' ने साधनावादी साहित्य की अवधारणा एवं उसकी सामाजिक-साहित्यिक प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए 'साधना वाणी' ई-पत्रिका के प्रकाशन और एक उल्लेखनीय एवं सार्थक पहल बताया। नीलचित्रा व्यास और डा. अनुराधा प्रियदर्शिनी ने साधना वाणी के प्रकाशन पर कहा कि उत्कृष्ट साहित्यिक प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सततअर्थ बढ़ाने के लिए आचार्य डॉ. मधुव्रत सभी को धन्यवाद एवं शुभकामनाएं दीं।

एतदुपरांत डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में साधना वाणी के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त की और साथ ही रचनाओं में स्तरीय रचनाओं का भविय में आमंत्रण हो, ऐसा सुझाव दिया तथा पटल के नियमों और अनुशासन की चर्चा की। कार्यक्रम में देव अतिथि के रूप में डॉ. छान लांग पंग विज्ञ जी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं एवं साधना वाणी की भूरि भूरि प्रशंसा की। अथवा जनता साधनावादी सूत्रधार न्यास के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश मिश्र ने साधनावादी सूत्रधन में साधना वाणी के प्रकाशन और सूत्रधन की मूलभूत आवश्यकताओं और सूत्रधन की बालिकाओं की ओर श्रद्धा करते हुए कहा कि मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि सूत्रधन की साधना हो और सूत्रधन से लोक मंगल हो। रचना से जीवन में लोक-मंगल का विधान हो। इसके उपरांत कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. पूर्णिमा पाण्डेय ने सभी अग्रागत अतिथियों का धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित किया।

लोकतंत्र और सरकार के बीच बढ़ता तनाव

जनता की आवाज़- विरोध प्रदर्शन और बदलते भारत की तस्वीर



आज हमारे देश में विरोध प्रदर्शन केवल सड़कों पर भीड़ जुटने या नारे लगाने तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इनके पीछे जनता की उम्मीदें, नाराजगी, अधिकारों की चिंता और सरकार से कई तरह के सवाल जुड़े हुए हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उनके अधिकारों पर अरसर पड़ रहा है, तब वे अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। यही आवाज़ कभी ख़ासों के रूप में सुनाई देती है, कभी किसानों के रूप में, कभी नौजवानों के रूप में और कभी राजनीतिक दलों तथा सामाजिक समूहों के रूप में। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जब जनता की आवाज़ और सरकार के फैसलों के बीच टकराव बढ़ने लगता है, तब यह सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में जनता की बात को उनकी ही अहमियत मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए।

अक्टूबर 2026 में देश की राजनीति दिग्भंग हो चुकाना आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज़नोना कुमार को लेकर एक बड़ा विवाद प्रदर्शन देखने को मिला है। इस प्रदर्शन में छात्रों, युवाओं, सामाजिक समूहों और विपक्षी दलों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। पत्रकारों की मुख्य मांग मतदाता सूची में किए जा रहे विशेष गहन पुरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर थी। चुनाव आयोग है कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और इससे लोगों के मतदान के अधिकार पर अरसर पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के हस्तोके की मांग भी कर रहे हैं। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मृत, दहे या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना है। इसलिए इस पूरे मामले में एक तरफ प्रदर्शनकारियों की आशंकाएँ हैं और

दूसरी तरफ चुनाव आयोग का अपना पक्ष है। इन आरोपों और दावों की निष्पक्ष जांच तथा सही जानकारी के आधार पर ही किसी विपक्ष के पड़चूना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सूरक्षा बढ़ाई गई, कई स्थानों पर रास्ते पर रोक लगाई गई और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं।

प्रदर्शनकारियों और कुछ विपक्षी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जबकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी है कि सरकार और प्रशासन की विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटना चाहिए तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि देश में होने वाले सभी विरोध प्रदर्शनों का कारण एक ऐसा नहीं होता। कई रोगाणु को लेकर युवाओं में नाराजगी है, कई परीक्षाओं में गड़बड़ी और पतन में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो उनके किसान अपनी फसल के उचित मूल्य और आर्थिक सुरक्षा की मांग करते हैं। कुछ जनता पर छात्र शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं, जबकि कुछ प्रदर्शन राजनीतिक फैसलों, सामाजिक न्याय या नागरिक अधिकारों से जुड़े होते हैं। इन सभी मुद्दों को एक ही नजर से देखना सही नहीं होगा, क्योंकि हर प्रदर्शन की अपनी परिस्थितियाँ, माँग और कारण होते हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी चिंताओं में रोगाणु और भविष्य की सुरक्षा भी शामिल है। पड़ोसी पूरे करने के बाद भी बहुत से युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती। सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाओं में देरी, प्रदर्शन लोक होने की शिकायतें, भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और परिणामों का हलभार युवाओं की परेशानी बढ़ते हैं। इन कई विषयों कई वर्षों तक मेहनत करता है, परिवार अपनी बचत उसकी पड़ोस और तैयारी पर खर्च करता है, लेकिन उन समस्या पर अरसर नहीं मिलता, तब निराशा होता न्यायप्रतिक है। ऐसे में जब युवा अपनी माँगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो उनकी माँग को केवल राजनीतिक विरोध कहकर नजरअंदाज करना उनकी वास्तविक समस्याओं को अनदेखा करना जैसा होगा।

सरकार की जिम्मेदारी है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, परीक्षाएँ समय पर हों और गलतियों की स्थिति में जवाबदेही तय की जाए। किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे भी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याएँ होती हैं। खेती में बीज, खाद, डीजल



और मजदूरी का खर्च बढ़ने पर किसान की कमाई पर अरसर पड़ता है। मौसम की मार, फसल का उचित दाम न मिलना और कर्ज का दबाव उसकी स्थिति को और कठिन बना सकता है। जब किसान अपनी माँगों को लेकर सरकार के सामने आते हैं, तो उनके पक्ष और सरकार के तर्कों को समझना जरूरी है। केवल विरोध करने वालों की गलत कहना या सरकार के हर फैसले को बिना सवाल सवाल मान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि बातचीत के माध्यम से ऐसा रास्ता निकले, जिससे किसानों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान हो सके। इसी तरह महंगाई भी आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। घर चलाने वाले परिवारों के लिए राशन, बिजली, किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और आने-जाने का खर्च महत्वपूर्ण होता है। जब आमदनी के मुक़ाबले खर्च बढ़ता है, तब परिवारों की अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो वह कानून के अनुसार, उचित और परिस्थिति के अनुसार भी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की ताकत केवल व्यवस्था चलाने में नहीं, बल्कि असमर्थता को सुनने और उसका समाधान करने में भी दिशाई देनी है। महत्वपूर्ण की भूमिका भी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सरकार से जवाब मांगना है। जब विपक्ष किसी मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाता है

करना और सरकार चुन लेना नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि जनता को अपनी बात कहने, सवाल पूछने, सरकार के फैसलों की आलोचना करने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार मिले। चुनाव के बाद भी सरकार जनता के प्रति

तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन विपक्ष से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह तथ्यों के आधार पर बात करे और जनता की वास्तविक समस्याओं को केवल राजनीतिक लाभ का साधन न बनाए। यदि किसी मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए

विरोध का उद्देश्य समस्या का समाधान होना चाहिए। हिंसा, नफ़रत, अफवाह और व्यक्तिगत दुश्मनी से किसी मुद्दे का सच्चा समाधान नहीं निकलता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तथ्यों पर बातचीत, न्यायिक प्रक्रिया और जिम्मेदार राजनीतिक चर्चा लोकतंत्र

एक राजनीतिक दल या केवल सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र जनता, संविधान, अधिकारों, जिम्मेदारियों और संस्थाओं के बीच संतुलन का नाम है। सरकार देश चलाने के लिए जरूरी है और जनता की आवाज़ सरकार को उसकी

प्रशासन की बात

जबकि प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। इस घटना ने एक बार फिर यह बहस शुरू कर दी है कि सरकार और प्रशासन को विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटना चाहिए तथा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि देश में होने वाले सभी विरोध प्रदर्शनों का कारण एक जैसा नहीं होता

जवाबदेही रहती है। जनता केवल वोटे देने वाली भीड़ नहीं है, बल्कि वही देश की अस्सी ताकत है। सरकार जनता की ओर से चुनी गई व्यवस्था है और उसका उद्देश्य लोगों के हित में काम करना है। इसलिए जब जनता कोई सवाल उठाती है, तो उनके लोकतंत्र के लिए खतार मतलब के बजाय उसे समझने की कोशिश की जानी चाहिए। हालाँकि, सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियाँ और सीमाएँ होती हैं। किसी भी देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आम नागरिकों की सुरक्षा करना और सार्वजनिक जीवन को सामान्य रखना प्रशासन का कर्तव्य है। यदि किसी प्रदर्शन की दौरान हिंसा होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है या आम लोगों के जीवन पर गंभीर अरसर पड़ता है, तो प्रशासन को कानून के अनुसार कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शांतिपूर्ण विरोध करने वालों के अधिकारों की अहंमियत भी नहीं होने चाहिए। कार्रवाई आवश्यक हो तो वह कानून के अनुसार, उचित और परिस्थिति के अनुसार भी चाहिए। लोकतंत्र में सरकार की ताकत केवल व्यवस्था चलाने में नहीं, बल्कि असमर्थता को सुनने और उसका समाधान करने में भी दिशाई देनी है। महत्वपूर्ण की भूमिका भी है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार के फैसलों पर सवाल उठाना, जनता की समस्याओं को सामने लाना और सरकार से जवाब मांगना है। जब विपक्ष किसी मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाता है

जाते हैं, तो उन आरोपों की जांच और प्रमाण जरूरी है। केवल आरोप लगा देने से कोई बात सच साबित नहीं होती और केवल आरोपों की खोज कर देने से भी सवाल समाप्त नहीं हो जाते। आज सोशल मीडिया ने विरोध अपनी परीक्षा को एक नया रूप दे दिया है। पहले किसी घटना की जानकारी लोगों तक पहुँचने में समय लगता था, लेकिन अब कुछ ही मिनटों में तस्वीरें, वीडियो और स्टिड देशभर में फैल जाते हैं। इससे लोगों को जानकारी मिलती है और वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ गलत जानकारी, अर्धे वीडियो और बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप भी तेजी से फैलते हैं। कई बार लोग पूरी घटना को बिना किसी एक पक्ष का समर्थन करने लगते हैं। इसलिए किसी भी प्रदर्शन या राजनीतिक विवाद की बारे में तथ्य जानने से पहले विश्वसनीय समाचार स्रोतों, आधिकारिक जानकारी और अलग-अलग पक्षों के बयानों को देखना जरूरी है। लोकतंत्र में जागरूक नागरिक होना केवल सवाल उठाना नहीं, बल्कि सही और गलत जानकारी के बीच अंतर समझना भी है। लोकतंत्र में असमर्थता का अपना महत्व है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक हर फैसले से सहमत हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी समस्याएँ समाप्त हो गईं। कई बार असमर्थता ही किसी कमी को सामने लाती है और व्यवस्था में सुधार का रास्ता खोलती है। इतिहास में भी जनता के अंदोलनों ने समाज और शासन से जुड़े मुद्दों को चर्चा के केंद्र में लाने का काम किया है। लेकिन

को मजबूत बना सकते हैं। सरकार को भी यह समझना चाहिए कि जनता की नाराजगी को केवल विरोधी राजनीति का परिणाम मान लेना पतन नहीं है। हर विरोध के पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो, यह जरूरी नहीं है। कोई छात्र अपनी परीक्षा और नौकरी के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकता है, कोई किसान अपनी फसल की कीमत को लेकर परेशान हो सकता है और कोई नागरिक अपने मताधिकार को लेकर आशंकित हो सकता है। उनकी समस्याओं को समझना और उनका उचित जवाब देना शासन की जिम्मेदारी है। दूसरी ओर, जनता और प्रदर्शनकारियों को भी यह समझना चाहिए कि किसी गंभीर आरोप को साबित करने के लिए प्रमाण, जांच और उचित कानूनी प्रक्रिया जरूरी है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों भी जुड़ी होती हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सरकार और जनता के बीच भरोसा कैसे बनाए रखा जाए। जब सरकार जनता की बात सुनती है, अपने फैसलों का कारण स्पष्ट करती है और गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहती है, तब लोगों का भरोसा मजबूत होता है। वही जब जनता को यह महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तब बातचीत के माध्यम से समाधान निकलने की संभावना बढ़ती है। इसके लिए केवल सरकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर काम करना, पारदर्शिता बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर जवाबदेही स्वीकार करना भी जरूरी है। अंत में यह कहना चाहिए कि लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति, किसी

जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। दोनों के बीच मतभेद होने अपने आप में लोकतंत्र की कमजोरी नहीं है, लेकिन जब बातचीत की जगह अड़थका और सवाल की जगह आरोप लेने लगते हैं, तब स्थिति घिटाजनक हो सकती है। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को समझते समय हमें न तो हर प्रदर्शन को गलत मानना चाहिए और न ही हर आरोप को बिना जांच के सही मान लेना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, लोगों की माँग क्या है, सरकार का पक्ष क्या है और समस्या का समाधान किस तरह निकाला जा सकता है। एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहाँ नागरिक बिना डर के सवाल पूछ सकें, सरकार उन सवालों की जवाब दे सकें और कानून सभी के लिए समान रूप से काम करे। क्योंकि अंत में देश केवल सरकार से नहीं चलता, देश जनता के विश्वास से चलता है। सरकार बदल सकती है, राजनीतिक दल बदल सकते हैं और समय के साथ नीतियाँ भी बदल सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र की अस्सी पहचान यही है कि जनता की आवाज़ सुनी जाए, उसके अधिकार सुरक्षित रहें और सत्ता को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। यही एक जागरूक समाज और मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

गंगा पाण्डेय
बाढ़, पटना